अर्जित निवल लाभ या हुई निवल हानि की निम्न स्थिति निम्न प्रकार है :—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	निवल लाभ (+) निवल हानि (—)
1981–82	(+) 2.38
1982–83	(—) 35.33
1983–84	(—) 279.05

वर्ष 1981–82 से 1983-84 के दौरान विभिन्न फसलों के संबंध में कुल उत्पादन और बीजों के उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1981–82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा किए गए कुल उत्पादन और बीजों के उत्पादन

(क्विंटल)

	1981–82		1982–83		1983–84	
फसलें	कुल	बीज	कुल	बीज	कुल	बीज
कपास	32282	13609	39397	13029	21047	5456
मूंग	5245	3832	10664	6340	6453	4127
चना	65841	36727	72144	40897	33977	24073
धान	59614	42144	59011	28795	47902	29816
गेंहू	104419	71166	131722	82493	128688	89553
सरसों	2806	1072	4573	1571	8287	5706
अन्य	51383	16995	80442	11242	51540	15619
कुल :	321590	185545	387953	184367	297894	174350

भारतीय खाद्य निगम के लाभ/हानि

1054. **श्री कैलाश पति मिश्र :**
श्री अश्विनी कुमार :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष-वार कितने मीटरी टन अनाज खरीदा/बेचा; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार हुये लाभ/हानि, खराब हो गए अनाज के प्रतिशत मूल्य और इसके रख-रखाव तथा सम्हलाई पर किये गये प्रतिशत खर्च का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और

चालू वर्ष में (जून तक) खरीदे और बेचे गये खाद्यान्नों की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

(मात्रा लाख मीटरी टनों में)

वर्ष	खरीदे गए खाद्यान्न	बेचे गए खाद्यान्न
1982-83	168.67	144.11
1983-84	175.65	143.35
1984-85*	159.94	122.05
1985-86* . . . . . (जून, 85 तक)	62.98	29.93

*वर्ष 1984-85 तथा चालू वर्ष के आंकडे अनन्तिम हैं और इनकी लेखापरीक्षा की जानी है।

(ख) सरकार की ओर से खाद्यान्नों के कारोबार पर भारतीय खाद्य निगम को देय राजसहायता को हिसाब में लेने के पश्चात्, 1981 से 1984 तक के वर्षों के दौरान कराधान से पूर्व कमाए गए निवल लाभ तथा हानियों की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	लाभ
1981-82	199.78
1982-83	529.72
1983-84	317.67

भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में खाद्यान्नों को सम्भालने में कुछ हानियां हो जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के किये गये कुल कारोबार की कुल मात्रा (खरीद+बिक्री) पर उन्हें हुई कुल हानि की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

वर्ष	(खरीद+बिक्री) के प्रति खाद्यान्नों की हानि की प्रतिशतता
1981-82	2.28
1982-83	2.37
1983-84	2.11

वर्ष 1984-85 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों को सम्भालने तथा उनके रख-रखाव का और उस पर किये गये खर्च का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

(रुपये/ क्विंटल)

वर्ष	वसूली विषयक प्रासांगिक खर्च		वितरण लागत	बफर स्टाक रखने की लागत
	गेहूं	चावल	गेहूं और चावल	
1982-83 . . .	24.28	9.94	43.91	42.23
1983-84 . . .	24.17	11.11	46.87	40.71
1984-85* . . .	28.09	17.57	48.34	43.82

*वर्ष 1984–85 के आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Sale of Babies in Orissa due to Poverty

1055. SHRI LAL K. ADVANI:

SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

SHRI KAILASH PATI MISHRA:

Will the Minister of AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in the 'Statesman' of the 27th June, 1985 stating that poverty in the country has increased to such an extent that some mothers in Kalahandi District of Orissa are selling their children so that those children and the parents may somehow keep themselves alive; and

(b) if so, what schemes are being implemented to emancipate the residents of such are in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) and (b) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Private Trade in Foodgrain

1056. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government propose to allow private trade in foodgrains to avoid substantial losses in handling and maintaining and also an expenditure of about Rs. 8,000 crores in maintaining huge stocks of grains with the Food Corporation of India and State Government agencies;

(b) if so, the details of the proposal; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) to (c) There is no ban on private trade in foodgrains within the country, except in the statutory rationing area of West Bengal.

Inclusion of more essential items for Public Distribution system

1057. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state·

(a) whether Government have issued directives to various State Governments to include some more essen-